बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 40 ● नई दिल्ली ● बुधवार 19 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिले जगदीप धनखड़; शपथ ग्रहण के बाद पहली बार औपचारिक मुलाकात

नई दिल्ली । पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है। बता दें कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये दोनों की पहली औपचारिक मुलाकात है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके अचानक इस्तीफे के बाद इस पद के लिए चुनाव हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि आलीशान उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में रहने वाले पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दोपहर राधाकृष्णन से मुलाकात की। सितंबर में सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से यह दोनों की पहली मुलाकात है।

रेखा गुप्ता ने 40 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आज़ादपुर में 40 नई इलेक्ट्रिक बसों और एक आधुनिक बस टर्मिनल को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और आदर्श नगर से भाजपा विधायक राजकुमार भाटिया भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ...आज का दिन इस सरकार की एक उपलब्धि है। यह बदलाव आपके वोट की ताकत से आया है। रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने विज्ञापनों की सरकार बनाई है, जो राजधानी में विकास लाने में विफल रही है।

उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान दिल्ली सरकार ने विज्ञापन नहीं, बल्कि प्रगति की है। उन्होंने कहा कि सालों से दिल्ली समस्याओं में उलझी रही... कोई सुनने वाला नहीं था... यह सिर्फ़ विज्ञापनों की सरकार थी... हमारी सरकार राजधानी के लिए रोज़ाना बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ लागू करती है... हमने कितने विज्ञापन लगाए? हम होर्डिंग भी नहीं लगाते... हम बस दिल्ली के लोगों तक नई पहल पहुँचाते हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार ने योजना लागू होने के बाद से आठ महीनों के भीतर 1,400 बसें उपलब्ध कराई हैं, जबकि पिछली सरकार 11 सालों में राजधानी में सिर्फ़ 2,000 बसें ही ला पाई थी। उन्होंने कहा कि आज हम दिल्ली को 40 इलेक्ट्रिक बसें और एक बस टर्मिनल दे रहे हैं... सिर्फ़ दो दिन पहले, हमने दिल्ली को 50 बसें दीं... आज हम 40 और दे रहे हैं... दिल्ली सरकार ने आठ महीनों के भीतर दिल्ली के लोगों को 1,400 बसें दी हैं... पिछली सरकार 11 सालों में सिर्फ़ 2,000 बसें ला पाई थी।

उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार ने न तो कूड़े के पहाड़ों की सुध ली और न ही सड़कों की खराब हालत की...जब से आपने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया है, हम चौबीसों घंटे दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। इस बीच, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने एएनआई को बताया कि नया बस टर्मिनल यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस है। उन्होंने कहा, हमने 40 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया है...यह आधुनिक बस टर्मिनल यात्रियों के लिए बनाया गया है...इस टर्मिनल से 116 बसें 21 जगहों पर जाएँगी...टर्मिनल में बैठने की व्यवस्था, खाने-पीने की व्यवस्था और शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए एआई का इस्तेमाल करेगा चुनाव आयोग, बंगाल से होगी शुरुआत

नई दिल्ली । चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि एआई की मदद से फर्जी और मृत मतदाताओं की पहचान की जाएगी। एआई तकनीक मतदाता डेटाबेस में तस्वीरों में चेहरे की समानता का विश्लेषण करेगी, जिससे कई जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि, मतदाताओं की तस्वीरों, खासकर प्रवासियों की तस्वीरों के गलत इस्तेमाल की शिकायतों में बढ़ोतरी के चलते हम एआई की मदद ले रहे हैं। उन्होंने कहा, एआई तकनीक से चेहरे मिलान तकनीक का इस्तेमाल उन मामलों का पता लगाने के लिए किया जाएगा जहां एक ही मतदाता की तस्वीर सूची में कई स्थानों पर दिखाई देती है। हालांकि, अधिकारी ने कहा कि बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) सत्यापन प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका में रहेंगे। उन्होंने कहा, एआई तकनीक सत्यापन में मदद करेगी, लेकिन तकनीक के इस्तेमाल के बावजूद, बीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। उन्हें घर-घर जाकर मतदाताओं की तस्वीरें लेनी होंगी। यहां तक कि जब बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) भरे हुए फॉर्म जमा करते हैं, तब भी बीएलओ को हस्ताक्षर सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से घर-घर जाना होगा। अधिकारी ने बताया कि, अगर गणना और फॉर्म भरने के बाद कोई फर्जी या मृत मतदाता पाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ की होगी। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा के चुनाव में ब्राजीली मॉडल के फोटो वाले पहचान पत्रों को लेकर खुलासा किया था। राहुल गांधी ने इन्हें लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि एआई तकनीक की मदद से अब किसी मतदाता की तस्वीर को दोबारा इस्तेमाल होने की आशंका बहुत कम हो जाएगी। चुनाव आयोग ने बीते महीने देश में दूसरे चरण में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया कराने की घोषणा की है। दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों को एसआईआर के अंदर कवर किया जाएगा। दूसरे चरण के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के अलावा अंडमान और निकोबार में एसआईआर होगा।

दुनिया के लिए भारत उभरता हुआ मॉडल, पीएम मोदी के भाषण के मुरीद हुए शशि थरूर

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही कांग्रेस नेता शशि थरूर के सुर बदले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद होने के बावजूद शशि थरूर अक्सर सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी समेत सरकार के कई फैसलों की सराहना करते दिखाई देते हैं।

हालांकि, उनके इस कदम से कांग्रेस के खेमे में भी खलबली मच जाती है। शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं, जिसके बाद सियासी पारा हाई होने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान को संबोधित करते हुए 2035 तक भारत को मैकाले की मानसिकता से निकालने की हुंकार भरी थी। पीएम मोदी के भाषण के दौरान ऑडियंस की कतार में शशि थरूर भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पीएम मोदी देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अब महज एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि दुनिया के उभरने की मिसाल बन चुका है। शशि थरूर ने आगे लिखा, पीएम मोदी ने कहा कि उनपर हमेशा चुनावी मोड में रहने का आरोप लगता है, लेकिन लोगों की समस्याओं पर बात करते हुए वो इमोशनल मोड में रहते हैं। मैकाले की 200 साल की विरासत गुलामी की मानसिकता पर प्रहार करना पीएम मोदी के पूरे भाषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा था। पीएम मोदी ने अगले 10 साल में भारतीय विरासत, भाषाओं और ज्ञान प्रणाली को गौरवपूर्ण तरीके से संवारने की अपील की है। शशि थरूर का कहना है, पीएम मोदी ने अपने भाषण में आर्थिक दृष्टिकोण के साथ-साथ संस्कृति को संवारने की हुंकार भरी। हालांकि, खांसी-जुकाम के बावजूद इस खास मौके पर दर्शकों के बीच बैठकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। बता दें कि पीएम मोदी के भाषण के दौरान शशि थरूर बीजेपी नेताओं के साथ बैठे थे। उनके बायीं ओर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बैठे थे और दायीं तरफ पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद थे।

दिल्ली दंगे राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने कहा- यह घटना सुनियोजित थी

नई दिल्ली । दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई दंगों पर चल रही कानूनी लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अदालत में साफ कहा कि यह हिंसा किसी भी तरह की सामान्य अशांति नहीं थी, बल्कि राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला था। पुलिस ने कार्यकर्ताओं उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का जोरदार विरोध किया और दावा किया कि यह घटना एक संगठित, सुनियोजित और पूर्व-नियोजित प्रयास का हिस्सा थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ के सामने दलील दी कि 2020 की हिंसा को अचानक भड़की भीड़ की प्रतिक्रिया बताकर महज नागरिकता कानून के विरोध तक सीमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भाषणों और बयानों का सिलसिला साफ दिखाता है कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश हो रही थी। मेहता ने अदालत में कहा कि यह किसी एक्ट के खिलाफ साधारण विरोध नहीं था। यह एक तैयार साजिश थी, जिसमें 'चक्का जाम' को पूरे देश में फैलाने की बात कही गई।

सोशल मीडिया नैरेटिव पर आपत्ति

मेहता ने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि युवा आरोपियों के खिलाफ कोई गंभीर और अन्यायपूर्ण कार्रवाई चल रही है, जबकि असलियत में ट्रायल में देरी के लिए आरोपी स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में मिले सबूत साफ दिखाते हैं कि दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं थे, बल्कि इन्हें एक चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था।

पुलिस ने जमानत का किया कड़ा विरोध

इस मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू भी दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में दलीलें रख रहे हैं। सुनवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की भूमिका मास्टरमाइंड जैसी थी और उन्हें जमानत देने से गलत संदेश जाएगा। पुलिस का यह भी तर्क है कि हिंसा को लेकर जुटाए गए सबूत किसी साधारण विरोध से कहीं अधिक गंभीर अपराधों की ओर इशारा करते हैं।

आरोपियों पर लगे ये आरोप

उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और रहमान पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने कहा कि ये लोग फरवरी 2020 की हिंसा के मुख्य योजनाकार थे, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पुलिस के अनुसार, यह हिंसा सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़की, लेकिन इसका मकसद केवल विरोध से कहीं आगे जाकर अस्थिरता पैदा करना था।

कब हुई थी हिंसा?

दिल्ली के पूर्वोत्तर इलाकों में हिंसा उस समय हुई थी जब नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में अब आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यह न केवल जमानत पर निर्णय तय करेगी बल्कि मामले की गंभीरता पर व्यापक टिप्पणी भी कर सकती है। अदालत में दलीलें जारी हैं और दिल्ली पुलिस का रुख बेहद सख्त बना हुआ है।

दिल्ली में दमघोंटू हवा का कहर जारी, कई इलाकों में एक्यूआई 600 के पार

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में मंगलवार (18 नवंबर) की सुबह लोग एक बार फिर घने स्मॉग की चादर में लिपटी हवा के बीच जागे. कई दिनों से लगातार 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हवा ने अब हालत और भी बिगाड़ दी है. सुबह 6:05 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 461 दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है. पिछले एक महीने से दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है और कृत्रिम बारिश कराने की कोशिशें भी अब तक किसी काम की साबित नहीं हुई हैं. दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में प्रदूषण का स्तर डराने वाला रहा. 17 नवंबर की सुबह दिल्ली का एक्यूआई 477 था, जो शाम होते-होते 548 पहुंच गया. अलीपुर, आनंद लोक, ग्रेटर कैलाश जैसे इलाके 580 से ऊपर रहे. वहीं पीजीडीएवी कॉलेज क्षेत्र में एक्यूआई 701 तक पहुंच गया, जो 'सीवियर प्लस' श्रेणी है और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. आनंद विहार और शाहदरा में भी एक्यूआई 608 दर्ज किया गया. स्थिति को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप का चौथा चरण यानी ग्रैप-4 लागू कर दिया है. यह प्रदूषण नियंत्रण का सबसे सख्त स्तर है. ग्रैप-4 लगते ही कई पाबंदियां लागू हो चुकी हैं. सभी तरह के निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक रहेगी. दिल्ली में ट्रकों की एंट्री लगभग बंद रहेगी. डीजल के भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. बड़े उद्योगों और प्लांट्स पर कड़ी निगरानी. सड़कों की मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा. इन सख्त कदमों का मकसद हवा में फैले धुएं को जल्दी कम करना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक हवा की रफ्तार नहीं बढ़ती, राहत मिलना मुश्किल है. दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री दर्ज किया गया. ठंड के साथ ही हवा की गति कम हो गई है, जिसके कारण प्रदूषण जमीन के पास ही अटक जा रहा है और फैल नहीं पाता. ऐसे में स्मॉग की परत और भी भारी होती जा रही है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि फिलहाल हवा की रफ्तार कम रहने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर थोड़ा और बढ़ सकता है. जहरीली हवा से लोगों में आँखों में जलन, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश जैसे लक्षण बढ़ रहे हैं. डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारियों वाले लोगों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है.

एनआईए को मिली आरोपी जसीर की 10 दिन की रिमांड, श्रीनगर से हुआ था गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के मामले में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की मांग पर कोर्ट ने आरोपी जसीर को 10 दिन की

हिरासत में भेज दिया है। जासिर बिलाल आतंकी उमर का सहयोगी है। उसकी रिमांड मिलने से जांच एजेंसी को धमाके के पीछे की साजिश का पता चल सकेगा। जसीर की गिरफ्तारी से ब्लास्ट के तार कश्मीर से जुड़ गए हैं। मालूम हो कि 10 नवंबर दिन सोमवार को शाम सात बजे के आसपास लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक कार धमाका हुआ था। इस आतंकी हमले में अब तक 15 लोगों की जान जान गई है, जबकि करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामले की जांच में एजेंसियों के हाथ कई सबूत लगे हैं। इसी क्रम में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जसीर भी उन्हीं में से एक है।

समाजवाद से दूरी ने कहीं का नहीं छोड़ा

बिहार में एनडीए की जीत को अपने-अपने नजरिए से देखा और विश्लेषित किया जा रहा है। बिहार में एनडीए की जीत के पीछे किसी को चुनाव आयोग की मिलीभगत दिख रही है तो किसी को सत्ता का दुरुपयोग तो कोई इसे भीतरघात के रूप में देख रहा है। लेकिन किसी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बिहार के पूरे प्रचार अभियान में सत्ता के दावेदार विपक्षी गठबंधन ने कितनी बार कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया, लोहिया की सप्त क्रांति की बात छोड़िए, कितनी बार जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की चर्चा हुई? यह सवाल इसलिए जरूरी और वाजिब लगता है, क्योंकि महागठबंधन की अगुआई जो राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है या कर रहा था, घोषित तौर पर लालू प्रसाद यादव उसके प्रमुख हैं। जो नहीं जानते हैं, उनके लिए यह बताना जरूरी है कि लालू यादव जिस आंदोलन की उपज माने जाते हैं, उस जेपी आंदोलन के अगुआ जयप्रकाश नारायण रहे हैं। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से थे और लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल घोषित तौर पर समाजवादी विचारधारा वाला दल है। जिस तरह लालू परिवार की सिरफुट्टौवल की बातें चारदीवारी से बाहर आ रही हैं, उससे साबित हो रहा है कि लालू अपनी पार्टी के सिर्फ कहने भर के अध्यक्ष हैं। पार्टी पर उनकी बजाय तेजस्वी यादव की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत है। एक तरह से कह सकते हैं कि तेजस्वी ही इस पार्टी के मालिक हैं। तेजस्वी जिन लोगों से घिरे हुए हैं, उन्हें तपी-तपाई समाजवादी विचारधारा से कुछ लेना-देना नहीं है। पार्टी भले ही घोषित रूप से समाजवादी हो, लेकिन हकीकत में पार्टी पर वामपंथी वैचारिक धारा का कब्जा है। तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज का नाम घर से बाहर निकाले गए तेजप्रताप यादव ने कभी खुलकर नहीं लिया, लेकिन घर से बेआबरू होकर निकली लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी ने दोनों का खुलकर नाम ले लिया है। वैसे बिहार में पहले से ही चर्चा थी कि तेजस्वी को इन्हीं दोनों नामों पर भरोसा है। पता नहीं, इन दोनों ने हाथ तेजस्वी कौन की नस दबी है, लेकिन अब साफ हो गया है कि परिवार की कीमत पर अगर तेजस्वी इन पर भरोसा करते हैं तो तय है कि इसके पीछे कुछ न कुछ गंभीर कारण जरूर है। उनकी सियासी प्रतिभा नहीं। अगर उनकी सियासी प्रतिभा होती तो बेशक तेजस्वी आज सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन कम से शर्मनाक हार के किनारे पर उनका दल नहीं पहुंचा होता। जनता दल से अलग राष्ट्रीय जनता दल गठित करते वक्त ही तय हो गया था कि समाजवादी दर्शन की खोल में राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद का परचम लहराने की कोशिश करेगा। उसने लहराया भी, लेकिन उसने गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के नाम का मुखौटा धारण किए रखा। 2025 का विधानसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव रहा, जिसमें ना तो टीवी और अखबारी चर्चाओं में इस दल ने लोहिया, जयप्रकाश या कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया, ना ही मैदानी चुनावी सभाओं में इस पर फोकस किया गया। राष्ट्रीय जनता दल का टेलीविजन चैनलों पर पक्ष रखने के लिए तीन महिलाएं आगे कर दी गई। प्रियंका भारती, कंचना यादव और सारिका पासवान को सौम्य और मृदु मृत्युंजय तिवारी और पढ़ाकू बौद्धिक मनोज झा के मुकाबले तवज्जो दी गई।

तीनों महिलाएं बहस कम, बदतमीजी ज्यादा करती दिखीं। उन्हें लगा कि दबंग आवाज में अपनी बात रखेंगी तो वह दूर तक सुनी जाएगी। इन्होंने अपने विपक्षी नेताओं को खुलेआम अपशब्द कहे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। आधुनिक टेलीविजन विमर्श के बड़े और गंभीर चेहरे सुधांशु त्रिवेदी से प्रियंका ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कंचना ने तो शुभ्रास्था के साथ सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया। प्रियंका और कंचना भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लालगढ़ के रूप में विख्यात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं। यह ठीक है कि जेएनयू पढ़ाई का संस्कार तो देता है, लेकिन उसका संकट यह है कि वह भारतीय समाज को वामपंथी चश्मे से देखने और समझने का जबर्दस्ती संस्कार थोप देता है।

इसलिए, यहां की वामपंथी राजनीति में पगा-डूबा छात्र समाज की हर समस्या के मूल को रामस्वामी पेरियार और महात्मा फुले के वैचारिक दर्शन के ही सहारे ढूंढता है और उनके ही सुझाए अतिवादी विचारों के जरिए उन्हें सुलझाने की समझ विकसित करता है। प्रियंका और कंचना जेएनयू की उसी परंपरा में पगी-डूबी छात्रा हैं, इसलिए वे बिहार के समाज को भी उसी अंदाज में समझ रही थीं और अपने हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल को उसी नजरिए से आगे बढ़ा रही थीं। इसका असर यह हुआ कि जिस बिहार की धरती से भारतीय समाजवाद ने राजनीतिक गलियारों तक की सफल यात्रा की थी, जिसके उत्तराधिकारी खुद लालू यादव भी रहे हैं, उस समाजवाद का सार्वजनिक विमर्श में भूले-भटके भी इस्तेमाल नहीं हुआ। जिस कर्पूरी ठाकुर की राजनीति के उत्तराधिकारी लालू रहे, उनका भी नाम नहीं लिया गया। जेपी और लोहिया की तो बात ही और है। सवाल यह है कि लालू की पार्टी का जो कट्टर समर्थक यादव समुदाय है, क्या वह सचमुच पेरियारवादी है, वह फुले के वैचारिक दर्शन को मानता है। पेरियार और फुले जिस ब्राह्मणवाद की कटु आलोचना करते हैं, राजनीति को छोड़ दें तो यादव समाज भी वास्तविक जीवन में उतना ही ब्राह्मणवादी है। वह भी हिंदू है और कई बार तो कथित सवर्ण समाज से भी कहीं ज्यादा हिंदू है। वह भी उसी तरह पूजा-पाठ करता है, उसी तरह धार्मिक है, उसी तरह पारिवारिक संस्कार करता है, जैसा बाकी कथित ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोग करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राम मंदिर की आलोचना करना, छठ पूजा पर सवाल उठाना क्या आम यादव समुदाय को स्वीकार्य हो पाया होगा? वैसे राबड़ी देवी ने छठ पूजा छोड़ दी है। लेकिन उनकी छठ पूजा भी कभी बिहार के मीडिया माध्यमों के लिए बड़ी खबर बनी रहती थी। तेजप्रताप को राजद के इस विचलन का पता था, शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपील कर दी थी कि अब तेजस्वी जी की पत्नी को छठ पूजा का व्रत शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि बिहार में सास से बहू छठ पूजा का उत्तराधिकार हासिल करती है। बहरहाल चुनाव नतीजों ने तो बता दिया कि बिहार में विपक्षी गठबंधन जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दूर करने की कोशिश कर रहा था या दूर मान रहा था, वह भी दरअसल उसकी सोच के दूसरे बिंदु पर खड़ा है। सवाल यह है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल से समाजवाद की विदाई क्यों हुई? इस सवाल का जवाब तलाशना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वामपंथी वैचारिकी के करीब होने के साथ ही तेजस्वी उस राहुल गांधी के भी करीब हैं, जिन्हें हर समस्या का समाधान वामपंथी सोच में ही नजर आता है। हिंदुत्व का विरोध उनका प्रमुख राजनीतिक दर्शन है। तेजस्वी भी यही कर रहे थे। इसे बढ़ावा देने में उनके सलाहकारों संजय यादव और रमीज ने भरपूर मदद दी है। प्रियंका, कंचना और सारिका जैसी बदमिजाज प्रवक्ताओं को प्रश्रय संजय यादव और रमीज की ही शह पर दिया गया। हर घर में सरकारी नौकरी देने का तेजस्वी के वायदे के पीछे वामपंथी अतिवादी वैचारिकी का ही हाथ रहा, नतीजा सामने है। बिहार की सत्ता छींका की तरह तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल से दूर हो गई है। पेरियार और फुले की वैचारिकी पर आधारित राष्ट्रीय जनता दल अगर आने वाले दिनों में बिखराव की ओर चल पड़े तो हैरत नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक बिखराव तो खैर शुरू हो ही चुका है।

सम्पादकीय...

गहरी चुनौतियों

बिहार का यह चुनाव केवल एक राजनीतिक मुकाबला नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की चेतना, जनता के विश्वास और नेतृत्व की विश्वसनीयता को परखने का अवसर भी था। परिणाम जिस तरह सामने आए, उन्होंने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश एवं दुनिया को चौंका दिया। यह जीत केवल गठबंधन की सामूहिक ताकत की नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्षों से स्थापित सुशासन मॉडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के अटूट भरोसे का परिणाम है। बिहार की महिलाओं ने इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई है- उनकी उम्मीदें, उनका साहस और उनका भरोसा इस परिणाम के मूल में खड़ा दिखाई देता है। बिहार में इतने एकतरफा नतीजे की उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। चुनाव प्रचार के दौरान जो लड़ाई टक्कर की दिख रही थी, वह आखिर में केवल भ्रम साबित हुई। जनता ने न महागठबंधन के बदलाव के नारे पर यकीन किया और न ही प्रशांत किशोर की अलग राजनीति पर भरोसा जताया, बल्कि खुद को परिपक्व एवं जागरूक प्रदर्शित करते हुए मूल्यों एवं विकास के मानकों पर मतदान दिया। आंकड़ों का विश्लेषण होता रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर यह परिणाम यह संदेश देता है कि अब बिहार जंगलराज नहीं चाहता, विकास की नई सुबह देखना चाहता है, एसआईआर को वोट चोरी के रूप में दी गयीप्रस्तुति उसे स्वीकार्य नहीं हुई, वह अतीत के भ्रष्ट शासन से मुक्ति के लिये अतीत की त्रासद यादों एवं भविष्य के सुनहरे भविष्य के बीच चयन करते हुए लालू-राबड़ी यादव के शासनकाल की की काली छाया नहीं चाहता। भले ही तेजस्वी यादव पूरे समय इसी नैरेटिव को तोड़ने में लगे रहे कि वक्त बदल चुका है और वह दौर अब नहीं लौटेगा। उन्होंने उल्टे अपराध पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो। नीतीश कुमार के लिए 20 बरसों में यह पहला विधानसभा चुनाव था, जहां वह गठबंधन का तो चेहरा थे, पर सीएम पद के उम्मीदवार नहीं थे। उनकी छवि को धुंधलाने एवं उन्हें बीमार घोषित करने के भी पूरे प्रयत्न हुए लेकिन, परिणाम ने साबित किया है कि नीतीश अब भी बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतीक एवं सुशासन-पुरुष है। वह अब तक नौ बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, कई बार उन्होंने पाला बदला, लेकिन जनता का यकीन उन पर बना हुआ है। इसकी बड़ी वजह उनकी बेदाग छवि भी है। लेकिन इस बार उनकी चुनौतियां भी बड़ी है। वैसे लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जीत जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां भी उतनी ही व्यापक हो जाती है। बिहार में एनडीए की इस ऐतिहासिक विजय के बाद जिस दौर की शुरुआत हो रही है, वह उत्साह से कहीं अधिक जिम्मेदारी का दौर है। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन रहे है, यह अपने-आप में निरंतरता, स्थिरता और सुशासन की अपेक्षाओं को नयी ऊंचाई देता है। परंतु अब उनके सामने जो प्रश्न खड़े है, वे कहीं अधिक गहरे, जटिल और चुनौतीभरे है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार केवल एक राजनीतिक पराजय नहीं, बल्कि परिवारवादी राजनीति के प्रति जनता की निर्णायक और स्पष्ट निष्पत्ति है। मतदाताओं ने यह संदेश दो टूक दिया है कि राजनीति किसी परिवार, वंश या व्यक्तिगत प्रभुत्व की जागीर नहीं हो सकती। खासकर क्षेत्रीय दलों में फैला वंशवाद, व्यक्तिवाद और उत्तराधिकार की अनिवार्य राजनीति जनता को लगातार विचलित करती रही है। परिणामों ने यह उजागर कर दिया कि अब मतदाता सिर्फ चेहरे और परिवारों के मोहजाल में नहीं फंसना चाहते, बल्कि वे विकास, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को प्राथमिकता देने लगे है। महागठबंधन की हार उसी व्यापक जनभावना का परिणाम है, जिसमें जनता ने यह तय कर दिया कि लोकतंत्र में जनता की सत्ता सर्वोपरि है, किसी भी राजनीतिक खानदान की नहीं। बिहार की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। वर्षों से यह राज्य बेरोजगारी के दर्द से जूझता रहा है। करोड़ों युवाओं की आंखों में नौकरी, अवसर और सुरक्षित भविष्य का सपना है। चुनावी वादे जिस उत्तेजना के साथ किए जाते है, उन्हें व्यवस्थित नीति, धैर्य और राजनीतिक ईमानदारी से लागू करना किसी भी सरकार के लिए आसान कार्य नहीं होता। लेकिन जनता ने इस बार उम्मीदों की जो गठरी सौंपी है, वह स्पष्ट संकेत है कि अब पूरा बिहार ठोस काम चाहता है, खोखले वादे नहीं। दूसरी बड़ी चुनौती कानून-व्यवस्था की है। सुशासन का मॉडल तभी सार्थक है जब आम नागरिक के जीवन में सुरक्षा की ठोस अनुभूति हो। अपराध, राजनीतिक संरक्षण, दंगा-फसाद और अराजकता किसी भी समाज की प्रगति को रोकते है। नीतीश कुमार से जनता की अपेक्षा है कि वे एक बार फिर वही कठोरता, वही व्यवस्था और वही संतुलित रणनीति लेकर आएंगे, जिसने कभी 'जंगलराज' को समाप्त कर सुशासन का नया इतिहास लिखा था। महिलाओं से किए गए वादे भी अब सरकार की प्राथमिक कसौटी बनेंगे। आधी आबादी ने जिस उत्साह और भरोसे के साथ एनडीए को पुनः सशक्त किया है, यह सरकार के लिए प्रेरणा के साथ-साथ उत्तरदायित्व भी है। सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान-ये पांच मुद्दे बिहार की महिलाओं की असली जरूरत है, और चुनावी वादों का मूल्यांकन भी अब इन्हीं पर होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था की मजबूती केंद्र सरकार के सहयोग पर भी निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके विकास-एजेंडे ने इस चुनाव को निर्णायक रूप दिया। जब केंद्र और राज्य की नीतियों में तालमेल होगा, तब ही आर्थिक सुधार, निवेश, उद्योग, रोजगार-सृजन और आधारभूत संरचना के बड़े सपने साकार होंगे। बिहार को अब केवल वित्तीय सहायता की ही नहीं, बल्कि विकास की स्थायी संरचना की जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित हो। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा प्रश्न मन को झकझोरता है-लोकतंत्र में चुनाव कब तक केवल 'सौदेबाजी' बने रहेंगे? कब तक वादों की भीड़, लुभावने नारों और जातीय समीकरणों के आधार पर जनता के विश्वास की खरीद-फरोख्त चलती रहेगी? आखिर लोकतंत्र की स्वस्थ दिशा क्या हो? यह चुनाव परिणाम हमें इस सवाल के सामने खड़ा करता है कि राजनीति को फिर से मूल्यों, दृष्टि, दीर्घकालिक योजनाओं और नैतिकता की ओर लौटना होगा। लोकतंत्र की प्रतिष्ठा तभी बचेगी जब राजनीति भविष्यदर्शी बने, जब चुनाव उत्सव कम और उत्तरदायित्व अधिक हो। बिहार, जिसे कभी पिछड़ेपन, गरीबी, पलायन और अपराध का प्रदेश कहा जाता था, आज भारतीय लोकतंत्र का एक जीवंत प्रयोगशाला बन गया है। यह प्रदेश भविष्य में किस दिशा में जाएगा, यह केवल सत्ता की नीतियों पर ही नहीं, बल्कि जनता की जागरूकता, मीडिया की ईमानदारी और राजनीतिक दलों की नैतिक प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करेगा।

बिहार में नई सरकार

बिहार में अब पुनः श्री नीतीश कुमार का मुख्यमन्त्री बनना तय है क्योंकि वर्तमान चुनावों में उनकी साख ने एनडीए को चुनाव जीतने में मदद की है। इसके साथ ही प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता ने भी एनडीए को भारी बहुमत दिलाने में सहायता की है। अतः इन दोनों नेताओं के इकबाल पर राज्य में लगातार एनडीए सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। श्री नीतीश कुमार बिहार के अकेले ऐसे मुख्यमन्त्री होंगे जिनका कार्यकाल सबसे लम्बा होगा और उनकी छवि भी एक सुशासन बाबू की होगी। उनकी सरकार ने जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं उनका असर इन चुनावों पर देखने को मिला है, हालांकि विपक्षी दल इन्हें रेवड़ियां भी बता रहे हैं मगर जनता ने इन्हें इस रूप में नहीं लिया है। बिहार में इस बार सत्तारूढ़ जनता दल व भाजपा के आपसी समीकरण पिछले चुनावों से बहुत भिन्न प्रकट हुए हैं। इसका कारण यह है कि इन दोनों दलों को लगभग बराबरढ्बराबर 89 व 85 सीटें प्राप्त हुई हैं। 243 की सदस्य संख्या वाली बिहार विधानसभा में इन दोनों पार्टियों का संख्याबल बताता है कि दोनों समान रूप से ताकतवर हैं जबकि पहले यह समझा जाता था कि राज्य में भाजपा की ताकत प्रभावी क्षेत्रीय दलों के मुकाबले कमजोर रहती है परन्तु पिछले 2020 के चुनावों में ही भाजपा ने 74 सीटें लाकर जद(यू) को बहुत पीछे छोड़ दिया था क्योंकि इसकी सीटें केवल 43 ही आयी थीं। 2020 में जो दोनों दलों की मिलीजुली सरकार बनी थी उसका आपसी गणित दूसरा था, मसलन इसमें भाजपा के मन्त्रियों की संख्या अधिक और जद(यू)के मन्त्रियों की संख्या आनुपातिक रूप से कम थी परन्तु इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वैसे भी दोनों ही पार्टियों ने इस बार के चुनावों में 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अतः दोनों के बीच बराबरी का भाव शुरू से ही था। मगर जहां तक सरकार के नेतृत्व का सवाल था तो श्री नीतीश कुमार निर्विवाद रूप से इसके नेता थे। ठीक यही स्थिति वर्तमान चुनावों के बाद भी बनी हुई है। इसका एक कारण और भी माना जा रहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार को लोकसभा में नीतीश कुमार की पार्टी का समर्थन प्राप्त है जो इस सरकार को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने में मदद करता है। अतः यह माना जा रहा है कि राज्य में जद(यू) व भाजपा के बीच सत्ता का बंटवारा बहुत न्यायप्रिय तरीके से होगा और मन्त्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी इसी के अनुरूप होगा।

एनडीए में इस बार श्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को भी 19 सीटें मिली हैं और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को पांच व उपेन्द्र कुशवाहा की आरएलपी को चार सीटें मिली हैं। अतः यह फार्मूला निकल रहा है कि चिराग की पार्टी को सरकार में दो मन्त्री पद दिये जायें और हम व आरएलपी को एक-एक। राज्य में सरकार का गठन अब 20 नवम्बर तक होना तय माना जा रहा है क्योंकि श्री नीतीश कुमार की निवर्तमान सरकार ने आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगली व्यवस्था होने तक वह कार्यवाहक मुख्यमन्त्री बने रहेंगे मगर यह व्यवस्था 20 नवम्बर को ही होने की उम्मीद है। इसकी एक वजह यह भी है कि आगामी 22 नवम्बर को निवर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्य में चुनाव इससे पहले ही पूरे हो चुके हैं और चुनाव आयोग ने नवनिर्वाचित 243 सदस्यों की तालिका राज्यपाल को सौंप दी है। अब नये विधायकों को सदस्यता की शपथ 20 नवम्बर के बाद दिलाई जायेगी। फिलहाल एनडीए सरकार के गठन का जो फार्मूला है उसके अनुसार नीतीश कुमार के नये मन्त्रिमंडल में जद(यू) व भाजपा के बराबर- बराबर मन्त्री होंगे और दो मन्त्री लोजपा के होंगे व एक जीतन राम मांझी व उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी के होंगे। इससे मन्त्रिमंडल का सन्तुलन बना रहेगा। मगर इस बार गृह व वित्त विभाग भाजपा के पास जायेगा। इसके साथ इस पार्टी के दो उप मुख्यमन्त्री होंगे या नहीं इसका फैसला भी अभी होना है। पिछली सरकार में भाजपा के विजय कुमार सिन्हा व सम्राट चौधरी दो उप मुख्यमन्त्री थे। ये दोनों नेता ही इन चुनावों में भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है तो इनके खिलाफ विपक्ष ने भ्रष्टाचार व कदाचार के गंभीर आरोप लगाये थे। विजय सिन्हा को भी विपक्ष ने आरोपों के घेरे में ले रखा था। मगर दोनों के चुनाव जीतने से यह सिद्ध हो गया है कि आम जनता ने इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया है। फिर भी भाजपा आलाकमान ने इस बारे में अभी कोई अन्तिम फैसला नहीं किया है। भाजपा राज्य में अपना कद्दावर क्षेत्रीय नेतृत्व भी पैदा करना चाहती है। अभी तक यह स्थान भाजपा में खाली पड़ा हुआ है। ऐसा भी माना जा रहा है कि भाजपा किसी नये नेता को उपमुख्यमन्त्री बना कर उस पर दांव लगा दे। पिछली सरकार में भाजपा के 22 मन्त्री थे तो जद(यू)के केवल 12 ही थे। मगर इस बार जद(यू) बराबर के मन्त्री रखेगी। देखने वाली बात होगी कि भाजपा गृह व वित्त विभाग के अलावा और किन महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखती है।

उम्र हमारी राह में कोई रोड़े नहीं अटकाती

पिछले दिनों एक खबर ने बहुत अच्छा महसूस कराया। खबर यों थी कि तमिलनाडु में अमुधावल्ली नाम की एक महिला रहती है। उनकी उम्र 49 साल है। उनकी 18 साल की बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी। इसलिए नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अमुधा बेटी को पढ़ते देखतीं, वह उसकी किताबें उठाकर पढ़ती रहतीं। बेटी के साथ-साथ उनके मन में भी इच्छा जागती। अंततः उन्होंने भी एक फैसला लिया। बेटी के साथ उन्होंने भी नीट का इम्तिहान दिया और परिणाम यह हुआ कि बेटी के साथ-साथ अमुधावल्ली ने भी नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली। अब मां-बेटी दोनों पढ़ाई साथ-साथ करेंगी और साथ-साथ ही डॉक्टर बनेंगी। यह एक मिसाल है कि अगर कोई कुछ करना चाहे तो कभी भी कर सकता है। उम्र उसमें कभी कोई बाधा नहीं बनती। बस खुद में हिम्मत और आत्मविश्वास लाने की जरूरत होती है। जब से यह खबर पढ़ी है, तब से न जाने ऐसी कितनी कथाएं दिमाग में कौंधने लगीं। जहां स्त्रियों ने बड़ी उम्र में अपने मन की करने की सोची और वे कामयाब रहीं। एक बिल्कुल अपने आसपास की घटना बताती हूं। यह वर्ष 1977 की बात है। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम के सामने खड़ी थी। वहां हम एक नाटक देखने आए थे। अब नाटक का नाम याद नहीं लेकिन कुछ घटनाएं जस की तस याद हैं। अभी नाटक शुरू नहीं हुआ था। हम बाहर ही खड़े थे। बहुत से परिचित आ-जा रहे थे। हम सब आपस में बातचीत कर रहे थे। तरह-तरह के व्यवसायों से जुड़े लोग थे। जैसे कि पत्रकार, अध्यापक, बैंकर आदि-आदि। लेकिन सबकी रुचि समान रूप से नाटक देखने में थी। तभी सामने से एक महिला आती दिखीं। उनके साथ एक बहुत बुजुर्ग महिला भी थीं, जिनका वह हाथ पकड़े थीं। बुजुर्ग महिला धीरे-धीरे चल पा रही थीं। चलते-चलते रुकतीं, फिर चलतीं। पास आकर वह महिला रुकीं तो पति ने परिचय कराया कि वह उनके साथ ही कालेज में पढ़ाती थीं। उनके साथ बुजुर्ग महिला उनकी मां थीं। पता चला कि बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ रहती है। पति गुजर गए हैं और बेटा पूछता नहीं। मां की परेशानी देखकर बेटी, उन्हें साथ ले आई। लेकिन बेटी की समस्या यह है कि जब वह काम पर निकल जाती है तो महिला अकेली रह जाती है। घरेलू सहायिका भी काम निपटाकर चली जाती है। जब तक बेटी लौटती है, वह अकेली ही रहती है। कितना टी.वी. देखें, कितना सोएं क्योंकि बेटी ने भी विवाह नहीं किया। मन है कि लगता नहीं। समझ में नहीं आता कि क्या करें। एक दिन बुजुर्ग महिला बालकनी पर खड़ी थीं तो वहां से उन्होंने कई लड़कियों को गुजरते देखा। वे सब इम्तिहान देने जा रही थीं। जब बुजुर्ग की कालेज में पढ़ाने वाली बेटी घर लौटी तो उन्होंने उससे कहा कि वह भी आगे पढ़ना चाहती हैं। बेटी को आश्चर्य हुआ। अब इस उम्र में कैसे पढ़ेंगी? क्या कालेज में एडमिशन लेंगी? बुजुर्ग महिला ने कहा कि नहीं वह प्राइवेट ही पढ़ेंगी।

प्राकृतिक चिकित्सा- आधुनिक युग में स्वास्थ्य, जागरूकता और जीवनशैली संतुलन का वैश्विक विमर्श

वैश्विक स्तरपर मानव सभ्यता के विकास के साथ चिकित्सा विज्ञान ने जितनी प्रगति की है,उतनी ही तेजी से जीवनशैली आधारित बीमारियाँ भी बढ़ी है।आज कैंसर,हार्ट अटैक,मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद,मोटापा और प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी जैसी बीमारियाँ वैश्विक चुनौती बन चुकी है। आधुनिक चिकित्सा जहाँ उन्नत उपचार प्रदान करती है,वहीं बीमारियों के मूल कारण, जीवनशैली ,तनाव,प्रदूषण गलत खान-पान और अनियमित दिनचर्या,को प्राकृतिक चिकित्सा ही सबसे सरल, सुरक्षित और प्रभावी रूप से संबोधित करती है। इसी बढ़ते महत्व के कारण हर वर्ष 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। यह दिन न केवल प्राकृतिक उपचार के विचारों का प्रसार है, बल्कि एक स्वस्थ, सशक्त और रोग-प्रतिरोधक समाज की नींव रखने की वैश्विक पहल भी है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि आज दुनियाँ जिस दिशा में जा रही है, वहाँ जीवनशैली जनित रोगों का स्तर अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर, मोबाइल, तनाव, नींद की कमी, बाहर का भोजन, प्रदूषण,और निष्क्रिय जीवनशैली ने शरीर को बीमारियों का घर बना दिया है।ऐसे समय में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रसार और प्रचार बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह सस्ती, सुलभ, बिना दुष्प्रभाव, और वैज्ञानिक आधार वाली चिकित्सा है,जिसका मुख्य उद्देश्य रोग को हटाना नहीं बल्कि स्वास्थ्य को स्थायी रूप से स्थापित करना है।प्राकृतिक चिकित्सा दिवस (18 नवंबर) की उत्पत्ति का उद्देश्य ही यह था कि देश और दुनियाँ के लोग अपनी जड़ों की ओर लौटें और नेचर केयरस अर्थात प्रकृति ही चंगा करती है,इस विचार को पुनर्स्थापित करें। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आधुनिक दवाइयाँ केवल बीमारी को दबाती है,परंतु प्राकृतिक चिकित्सा बीमारी के कारण को मिटाती है। साथियों बात अगर हम प्रकृति-सबसे बड़ी हीलर और संतुलित जीवनशैली,सबसे बड़ी दवा इसको समझने की करें तो,मनुष्य जब प्रकृति से दूर होता है तो बीमार पड़ता है, और जब वह प्रकृति के पास लौटता है तो बिना दवा के भी स्वस्थ हो जाता है। यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल मंत्र है। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, धूप, मिट्टी और भोजन दिया,ये पाँच तत्व ही असली डॉक्टर है। संतुलित जीवनशैली, नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार पर्याप्त आराम, मानसिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी आधुनिक दवा से अधिक प्रभावी साबित होती है।प्रकृति का हीलिंग प्रभाव वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध है- (1) वनस्पतियों के बीच रहने से स्ट्रेस हार्मोन 40 प्रतिशत तक कम हो जाता है(2)सूर्य किरणें डी-रोल्स और इम्यून कोशिकाओं को सक्रिय करती है (3) मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स मानसिक अवसाद कम करते है (4) जंगल की हवा एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है (5) प्राकृतिक वातावरण रक्तचाप और नाड़ी की गति को सामान्य करता है इसलिए कहा जाता है,अगर जीवन संतुलित है तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर जीवन असंतुलित है तो दवा भी पूरी तरह लाभ नहीं देती। साथियों बात अगर हम,दिनचर्या और जीवनशैली में सुधार द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है,इसको समझने की करें तो मानव शरीर अद्भुत है।इसमें स्वयं को ठीक करने की क्षमता जन्मजात होती है। लेकिन आज का जीवन,तेज गति, तनाव प्रदूषण, देरतक जागना फास्ट फूड और मानसिक दबाव,इस प्राकृतिक क्षमता को कमजोर कर देता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए जीवनशैली सुधार सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक तरीका है। (1) सूर्योदय के साथ दिनचर्या की शुरुआत- सुबह की धूप विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है, जो इम्यून सिस्टम को अत्यधिक सशक्त बनाता है। सूर्योदय के समय वायु शुद्ध होती है और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। (2) प्राकृतिक आहार पर आधारित भोजन-कच्चा भोजन, मौसमी फल,अंकुरित अनाज, सलाद हरी सब्जियाँ, नारियल पानी, नींबू, फाइबर और कम तेल वाला भोजन शरीर को शुद्ध करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।(3)जल का संतुलित सेवन- शरीर में 70 प्रतिशत पानी होता है। सुबह गुनगुना पानी पीना, जल- चिकित्सा और पर्याप्त हाइड्रेशन शारीरिक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। (4) श्वास और योग अभ्यास-रेगुलर प्राणायाम, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और ध्यान,मानसिक तनाव कम करते है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाते है। (5) पर्याप्त नींद-7-8 घंटे की नींद हार्मोन संतुलन बनाती है, अवसाद कम करती है और प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करती है। (6) तनाव प्रबंधन-मेडिटेशन, संगीत, प्रकृति में समय, पेड़-पौधों के बीच चलना, और डिजिटल डिटॉक्स तनाव से मुक्ति के श्रेष्ठ उपाय है। (7) सक्रिय दिनचर्या-चलना, तैरना, हल्का व्यायाम, गार्डनिंग, ये सभी इम्यून सेल्स को सक्रिय रखते है। इन आदतों के माध्यम से शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत बनता है और गंभीर बीमारियों से बचाव की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। साथियों बात अगर हम कैंसर और हार्ट अटैक जैसी भयानक बीमारियों में प्राकृतिक चिकित्सा का योगदान-विज्ञान, व्यवहार और संभावनाएँ इसको समझने की करें तो,कैंसर और हार्ट अटैक आधुनिक जीवनशैली से उत्पन्न सबसे गंभीर बीमारियों में शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनियाँ में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे है और हृदय रोग आज भी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है।यद्यपि इन बीमारियों का प्रत्यक्ष इलाज आधुनिक चिकित्सा के माध्यम से ही संभव है, लेकिन इनकी रोकथाम, जोखिम कम करने और उपचार के बाद स्वस्थ होने की प्रक्रिया में प्राकृतिकचिकित्सा अत्यंत प्रभावी रूप से कार्य करती है।प्राकृतिक चिकित्सा मूलतः शरीर की अपनी चिकित्सकीय शक्ति को सक्रिय करने पर आधारित विज्ञान है।

इसमें पाँच प्रमुख तत्व,जल, वायु, धूप, मिट्टी और आहार,को संतुलित उपयोग के माध्यम से शरीर को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। कैंसर के संदर्भ में प्राकृतिक चिकित्सा सूजन को कम करने, टॉक्सिन हटाने, हार्मोन संतुलन, और मानसिक तनाव घटाने में अद्भुत प्रभाव डालती है। कई शोध यह बताते हैं कि प्राकृतिक भोजन, ऑर्गेनिक आहार, योग, सूर्य स्नान, जल चिकित्सा और भावनात्मक संतुलन कोशिकाओं की उम्र बढ़ने और डीएनए क्षति को कम कर सकते हैं,जो कैंसर के प्रमुख कारणों में से है।हार्ट अटैक की रोकथाम में भी प्राकृतिक चिकित्सा एक स्तंभ के समान है। डॉ. डीन ऑर्निश और अन्य वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जीवनशैली सुधार,खान-पान, मेडिटेशन, गहरी श्वास, प्राकृतिक आहार और तनाव प्रबंधन,हृदय की धमनियों में जमा वसा को कम करने में सहायक हो सकता है। 'नेचर क्योर' की पद्धति रक्तचाप को नियंत्रित करती है, कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करती है और शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करती है। इस प्रकार यह कहना बिल्कुल उचित है कि प्राकृतिक चिकित्सा कैंसर और हार्ट अटैक के प्रत्यक्ष इलाज की जगह नहीं, बल्कि इनके खिलाफ प्रभावी सुरक्षा कवच है,जो लंबे समय तक बीमारी से बचाव और उपचार के बाद स्वस्थ रहने की शक्ति विकसित करती है। साथियों बात अगर हम लोगों में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता क्यों आवश्यक है और 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस क्यों मनाया जाता है इसको समझने की करें तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है- (1)सरल जीवनशैली अपनाने का संदेश देना (2) लोगों को दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता से बचाना (3) प्राकृतिक भोजन, योग, प्राणायाम और धूप के महत्व को समझाना (4) बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में स्वास्थ्य सुरक्षा की संस्कृति विकसित करना (5) समाज में रोकथाम- आधारित चिकित्सा की सोच को मजबूत करनाभारत सरकार ने 2025 में इसे विशेष रूप से 8 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि अधिकाधिक जनभागीदारी बढ़े और लोग प्रकृति- आधारित जीवनशैली के प्रति प्रेरित हो। यह न केवल एक दिवस है बल्कि एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य आंदोलन है।वर्ष 2025 में 8 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। यह दिन प्राकृतिक चिकित्सा को सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के महत्वपूर्ण आधार के रूप में निहित करता है। इस अवसर पर देशभर में अनेक आयोजन किए जाते है- (1) हेल्थ कैंप (2) निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर (3) योग एवं ध्यान कार्यशालाएँ (4) प्रकृति आधारित जीवनशैली से संबंधित संगोष्ठियाँ (5) स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम (6) महिलाओं, बुजुर्गों और युवा वर्ग के लिए विशेष प्रशिक्षण (7) प्राकृतिक चिकित्सकों द्वारा मार्गदर्शन (8) स्वास्थ्य यात्रा और जन-जागरण रैलीआयोजित की जाएँगी।इसका लक्ष्य यह संदेश देना है कि स्वास्थ्य का मूल मंत्र दवाओं में नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवनशैली के समन्वय में है। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, निरोगी और जागरूक भारत की नींव रखेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कल्पना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/30, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08862)

वोटर लिस्टों में शामिल होंगे सभी पात्र मतदाताओं के नामः भूपेन्द्र सिंह

मुरादाबाद। भाजपा ने नगर विधानसभा में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) पर एक कार्यशाला आयोजित की। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चैधरी ने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने चाहिए. भाजपा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) पर एक कार्यशाला नगर विधानसभा में की। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चैधरी ने जोर दिया कि कोई पात्र मतदाता इसमें छूटने नहीं पाए। सभी जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी भूमिका निभाएं। सोमवार रात 8 बजे दिल्ली रोड स्थित क्लासिक बैंक्वट हाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चैधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का यह सबसे महत्वपूर्ण अभियान है।

एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस गम्भीर

मुरादाबाद।

दिल्ली स्तिथ कांग्रेस मुख्यालय पर एसआईआर को लेकर हुई बैठक में जिले की सभी विधान सभा सीटो पर भी चर्चा हुई। हाईकमान ने बूथ परिवर्तन एवं परिवर्धन को लेकर जिलाध्यक्ष से सतर्कता बरतने को कहा। इस दौरान जिलाध्यक्ष यहाँ मतदाता सूची पुनरीक्षण की जानकारी नेताओं को दी। मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी व महासचिव अविनाश पाण्डेय ने दिल्ली में यूपी के नेताओं को तलब किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अलावा राष्ट्रीय सचिव धीरज गुजर,प्रदीप नरवाल, प्रवक्ता पवन खेड़ा, राजीव शुक्ला के अलावा सांसद इमरान मसूद सरीखे तमाम नेता मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर ने कहा कि पार्टी एसआईआर के मुद्दे पर बेहद गम्भीर रुख अपनाए हुए है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडेय ने कहा है कि भाजपा विपक्षी वोटो को कम करने के लिये इस अभियान को हथियार बना रही है। कांग्रेस के नेता टेबिलों पर बैठकर ही वोटर लिस्ट न मिलाए बल्कि घर घर जाकर मिलान करें। जिलाध्यक्ष के मुताबिक उन्होंने बूथों की संख्या बढ़ाने में भी कार्यकर्ताओं से बारीकी समझने के निर्देश दिये। गड़बड़ी की आशंका होने पर तत्काल आपत्ति दाखिल किये जाने को कहा। जिलाध्यक्ष गुम्बर ने लगे हाथ यहां वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर चल रही पार्टी की गतिविधियों की जानकारी राष्ट्रीय महासचिव, सचिवों व प्रदेश अध्यक्ष को दी। इस दौरान उनके साथ फुरकान लम्बरदार व राजा भी रहे।

रालोद ने उठाईं एसआईआर में आ रहीं समस्याएं, डीएम को दिया ज्ञापन

मुरादाबाद।

राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) महानगर के पदाधिकारियों ने मंगलवार जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र सौंपा। इस पत्र के माध्यम से मतदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आ रही समस्याओं से अवगत कराया गया। रालोद के रोहिलखंड क्षेत्रीय महासचिव सैयद राशिद अली ने बताया कि मतदाता एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इन समस्याओं के तत्काल समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। पत्र में मुख्य रूप से कई समस्याओं का उल्लेख किया गया है। इनमें वेबसाइट से आवश्यक दस्तावेज डाउनलोड न हो पाना, बीएलओ द्वारा फॉर्म की कॉपी की रसीद न देना जिससे फॉर्म स्वीकार होने का प्रमाण नहीं मिल पाता, और फॉर्म भरते समय बार-बार खराब होने या फोटोस्टेट की समस्या शामिल हैं।रालोद ने मांग की है कि बीएलओ को मतदाताओं को सही सलाह देने और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने बताया कि कई बीएलओ अभी भी पुराने 2003 के फॉर्म भरवा रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग द्वारा केवल वर्तमान फॉर्म ही मान्य हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने जिला निर्वाचन अधिकारी से इन समस्याओं का संज्ञान लेने और तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है, ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने फॉर्म जमा कर सकें। इस दौरान सैयद राशिद अली, जकी अहमद, सलीम कुरैशी,सलीम खां, नौशाद अली आदि मौजूद रहे।

डायट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रशिक्षण में गूँजे नए तकनीकी मंत्र

फतेहपुर।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बुधवार को 200 शिक्षकों का पांच दिवसीय एकीकृत प्रशिक्षण शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डायट प्राचार्या/उप शिक्षा निदेशक आरती गुप्ता ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों का शैक्षिक स्तर और बेहतर हो इसलिए समय-समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षकों को लगातार सीखने की जरूरत होती है। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षकों को भी समय के साथ अपडेट रहना चाहिए। कहा कि शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी, और छात्रों की बदलती जरूरतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। प्रशिक्षण में प्रवक्ता संजीव सिंह ने प्रशिक्षण की रूपरेखा के बारे में बताते हुए कहा कि प्रत्येक सत्र महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने, छात्रों को सीखने में मदद करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार प्रशिक्षण के सत्रों का उद्देश्य है। प्रवक्ता भारती सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण कौशल में परिमार्जन करना होगा। प्रवक्ता अतुल कुमार ने अध्यापकों को नई शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तन से परिचित कराया। कहा कि इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और समावेशन में सुधार करना है, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर ध्यान केंद्रित करना है। डॉ रमेश कुमार सोनकर ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं खेल के विषय पर विस्तार से बताते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास की जिम्मेदारी हम शिक्षकों पर है। प्रशिक्षण प्रभारी प्रवक्ता विनय कुमार मिश्र ने बताया कि पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को उनके विषयों में नई शिक्षण तकनीकों और उपचारात्मक शिक्षण विधियों को बताया जा रहा है। जिससे जिले के विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाया जा सके।

संस्कृति-नवाचार महोत्सव बना डायट का महाकुंभ, कौशल-कला और कल्पनाओं की बड़ी भिड़ंत

फतेहपुर।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में कला, क्राफ्ट एवं संस्कृति महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्या आरती गुप्ता, नोडल प्रभारी प्रवक्ता मानवेन्द्र सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं में रचनात्मकता, अभिव्यक्ति कौशल तथा भारतीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना था। इस आयोजन में जिला के शिक्षकों एवं डायट के प्रशिक्षुओं एवं अमौली, असोथर, ऐरायां, खजुहा, बहुआ, धाता और मलवां ब्लॉक के शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया और अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में आयोजित प्रमुख गतिविधियाँ चित्रकला प्रतियोगिता, हस्तकला एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी वाल पेंटिंग,पपेट शो अभिनव रंगमंच,सांस्कृतिक नृत्य एवं गीत प्रस्तुति स्थानीय लोक-संस्कृति आधारित मॉडल प्रदर्शनी शिक्षकों तथा प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत पेंटिंग, मॉडल और विभिन्न क्राफ्ट आइटम्स ने सभी आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के दौरान लोकनृत्य, समूहगान व नाट्य मंचन ने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। प्राचार्या आरती गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से रचनात्मक सोच, सांस्कृतिक समझ तथा प्रस्तुतीकरण कौशल में वृद्धि होती है। उन्होंने सभी प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों, प्रशिक्षुओं एवं आयोजन समिति को हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता शाइस्ता इकबाल द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। अंत में प्रथम दिवस के प्रतिभागियों को प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। नोडल प्रभारी प्रवक्ता मानवेन्द्र सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के कलात्मक और रचनात्मक कौशल के विकास की अनुशंसाओं का सफल क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से क्राफ्ट एवं संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो निपुण लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। गुरूवार को बचे हुए सात ब्लाकों के शिक्षकों के द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।इस अवसर पर डायट प्रवक्ता विनय कुमार मिश्र, प्रवक्ता राजेंद्र कुमार, के अलावा डीएलएड प्रशिक्षु आदि उपस्थित रहे।

11 बेटियों के सामूहिक विवाह करायेगी संस्था

मुरादाबाद।

आओ हाथ बढ़ाएं संस्था की की ओर से 11 बेटियों के सामूहिक विवाह का आयोजन 20 नवम्बर को किया जायेगा। इससे पूर्व आज बेटियों की हल्दी, मेहंदी और महिला संगीत का शानदार कार्यक्रम दिल्ली रोड स्थित एक उत्सव मंडप में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में सभी बेटियों को एक से वस्त्र साड़ी, आभूषण, श्रृंगार, हल्दी एवं मेहंदी आदि लगाकर उनको यह एहसास ही नहीं होने दिया कि वह अपेक्षाकृत विपन्न परिवारों से हैं, बल्कि बड़े से बड़े घरों के विवाह उत्सव भी इसके सामने फीके नजर आएंगे! आज उपस्थित उत्तम समाज बेटियों एवं महिलाओं ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां देकर माहौल को खुश गवार बना दिया, अंत में सुरुचि पूर्ण भोज की व्यवस्था भी थी।

कार्यक्रम का संयोजन और निर्देशन बहन गीतांजलि पाण्डेय द्वारा किया गया, उनकी समस्त टीम को हार्दिक बधाई, साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद, उन्हें सामाजिक समरसता के ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित होकर सदैव बहुत अच्छा लगता है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष, जिला अध्यक्ष के खिलाफ 116 वरिष्ठ नेताओं का सामूहिक विरोध

बहराइच।

जनपद के 116 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं एवं पदाधिकारियों ने आज एक सामूहिक आपत्ति एवं चेतावनी पत्र जारी करते हुए प्रदेश नेतृत्व द्वारा की गई हालिया जिला अध्यक्ष नियुक्ति को अन्यायपूर्ण, मनमाना व संगठनविरोधी करार दिया है। नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि निर्णय वापस न लिया गया और जिले का अध्यक्ष बदला नहीं गया, तो सभी नेता व कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। नेताओं ने कहा कि यह पत्र ÷गहरी पीड़ा, आक्रोश और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के खिलाफ एक संघर्ष÷ के रूप में लिखा गया है। पूर्व जिलाध्यक्षों, पीसीसी सदस्यों, ब्लॉक अध्यक्षों, नगर अध्यक्षों, जिला-महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल व युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की बड़ी संख्या ने हस्ताक्षर कर इस निर्णय का विरोध किया है। सभी वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट कहा कि जिला अध्यक्ष का कोई संगठनात्मक अनुभव नहीं है। पद ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जो

कभी पार्टी की किसी जिम्मेदारी पर नहीं रहा, जिससे जमीनी कार्यकर्ता आहत हैं।वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर मनमानी नियुक्ति की गई। पूर्व जिलाध्यक्ष जय प्रकाश मिश्र, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अमर नाथ शुक्ल व किसान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नेम कुमार चौहान जैसे अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर एकतरफा निर्णय थोप दिया गया है।इस निर्णय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, जिससे संगठन में मेहनत करने वाले वरिष्ठ, युवा और महिला पदाधिकारियों में भारी असंतोष है। इन र्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व से तीन प्रमुख मांगें रखी हैं,अनुभवी कांग्रेसजनों के निष्कासन को तुरंत रद्द किया जाए, बहराइच जिला अध्यक्ष को तुरंत बदला जाए और संगठन संभालने के योग्य, जमीनी और सर्वमान्य नेता की नियुक्ति की जाए। पत्र में सभी नेताओं ने साफ कहा है कि यदि इस अन्यायपूर्ण निर्णय को बदला न गया तो वह सभी इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। इस पत्र पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष, पीसीसी सदस्य, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और विभिन्न विंगों के कुल 116 नेताओं के हस्ताक्षर हैं। यह बहराइच जनपद के कांग्रेस इतिहास में सबसे बड़ा सामूहिक विरोध माना जा रहा है। मुख्य रूप से एआईसीसी सदस्य, नि. प्रदेश सचिव व पयागपुर वि. स. के पूर्व प्रत्याशी मेजर राना शिवम सिंह, एआईसीसी सदस्य व मटेरा वि. स. के पूर्व प्रत्याशी अली अकबर पप्पू, नानपारा वि. स. के पूर्व प्रत्याशी व पीसीसी सदस्य डॉ. ए एम सिद्दीकी, महसी वि. स. के पूर्व प्रत्याशी व पीसीसी सदस्य डॉ. राजेश तिवारी, निवर्तमान शहर अध्यक्ष आदर्श अग्रवाल, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हाजी महफूज अहमद, पूर्व शहर उपाध्यक्ष दिलीप शर्मा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुकुंद जी शुक्ल, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुनऊ मिश्र, पूर्व जिला महासचिव, राघवेंद्र द्विवेदी, पूर्व युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव रवि श्रीवास्तव, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव नदीम अहमद, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष कुंवर साहब श्रीवास्तव, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपुल मिश्र, महिला जिलाध्यक्ष कमला सोनी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष मो. फरीद हुसैन, सेवादल कार्यवाह जिलाध्यक्ष राम कुमार यादव, अनुसूचित विभाग जिलाध्यक्ष गोविंद गौतम, महिला शहर अध्यक्ष इरम ठाकुर, प्रदेश महासचिव मानवाधिकार प्रकोष्ठ गोवर्धन लाल अवस्थी, पूर्व जिला महासचिव दिवाकर पांडेय, पूर्व जिला महासचिव अखिलेश त्रिपाठी, पूर्व जिला महासचिव महिपाल सिंह सहित 116 पदाधिकारियों ने पत्र लिखा है।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश में खोए और चोरी किये गये सेकड़ों मोबाइल फोन बरामद, राष्ट्रीय रिकवरी दर में 31फीसदी से अधिक सुधार

नई दिल्ली। देश भर में मोबाइल चोरी और गुम होने के बढ़ते मामलों के बीच, एक सकारात्मक रुझान दिखने लगा है। मोबाइल छिन जाना, खो जाना, या गिर जाना, चोरी हो जाना, इस तरह की वारदातें काफी आम है। न जाने कितने लोगों के मोबाइल रोजाना चोरी हो जाते हैं। एक कुछ समय में जिस तरह से मोबाइल से जुड़े साइबर अपराध बढ़े है पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो गयी है। दिल्ली पुलिस ने खोए व चोरी किये गये 152 मोबाइल फोन बरामद किए और एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने एक बयान में बताया कि मोबाइल फोन में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय विवरण व महत्वपूर्ण डेटा होते है और इनके खो जाने से अक्सर काफी परेशानी होती है। पुलिस के मुताबिक, पिछले वर्षों में सीमित बरामदगी के कारण नागरिकों में यह धारणा बन गई थी कि खोए हुए फोन का पता लगाना पुलिस की प्राथमिकता नहीं है। बयान में बताया गया कि इस धारणा को दूर करने के लिए पुलिस ने 152 मोबाइल फोन का पता लगाकर उन्हें बरामद किया और उन्हें उनके असली मालिकों को लौटा दिया। अधिकारी ने बताया कि इस पहल का नेतृत्व एक विशेष महिला टीम द्वारा किया गया, जिसने तकनीकी उपकरणों व दूरसंचार विभाग के केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल

का उपयोग कर फोन का पता लगाया। वहीं दूसरी तरफ पिछले चार महीनों में, चोरी हुए और खोए हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अगस्त और नवंबर 2024 के बीच, राज्य पुलिस बलों और डिजिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के समन्वित प्रयासों से हजारों नागरिकों को उनके खोए हुए डिवाइस वापस पाने में मदद मिली। इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मोबाइल रिकवरी दर में 31.71फीसदी का सुधार हुआ, जो हाल के वर्षों में दर्ज की गई सबसे बड़ी उछाल है। देश की औसत रिकवरी दर लगभग 27फीसदी है, लेकिन कई राज्यों ने उल्लेखनीय रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार और झारखंड, संख्या और दक्षता दोनों के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। कुल मिलाकर, इन चार महीनों के दौरान 1.66 लाख से ज्यादा मोबाइल फोनों का पता लगाया गया और उन्हें वापस किया गया। उत्तर प्रदेश कुल संख्या के हिसाब से सूची में सबसे ऊपर रहा, जहाँ 17,600 से ज्यादा फोन बरामद हुए, जो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद करना स्वाभावतः अन्य चोरी हुई वस्तुओं को खोजने की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। फोन अक्सर एक शहर में चोरी होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में दूसरे राज्य में सक्रिय हो जाते है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में चोरी हुआ कोई उपकरण बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या उत्तर प्रदेश के किसी दूरदराज के कस्बे में सक्रिय पाया जा सकता है।

कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में करेगी बड़ी रैली

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार के एसआईआर का कांग्रेस शुरुआत से ही विरोध कर रही है. अब कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली निकालने जा रही है. यह रैली दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी. रैली का ऐलान एसआईआर पर कांग्रेस की बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया है. दरअसल एसआईआर वाले राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में राहुल गांधी और खरगे शामिल हुए थे.

कांग्रेस का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप

कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी और पीएम मोदी के लिए काम कर रहा है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे लेकर सभी को आगाह किया था. वहीं केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की नियत लोकतंत्र और विपक्षी दलों को खत्म करने की है. वहीं खरगे ने

कहा कि कांग्रेस वास्तविक मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने के हर प्रयास का पर्दाफाश करेगी. वह लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों का क्षरण नहीं होने देगी.

एसआईआर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश

मल्लिकार्जुन खरगे ने बैठक में कहा कि निर्वाचन आयोग को यह साबित करना होगा कि वह बीजेपी की छाया में काम नहीं कर रहा है. उन्होंने यह दावा भी किया कि बीजेपी एसआईआर का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने की कोशिश कर रही है और अगर आयोग इसकी उपेक्षा करता है तो उसकी भी संलिप्तता मानी जाएगी.

एसआईआर पर कांग्रेस की अहम बैठक

खरगे ने उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद जारी है. पार्टी मुख्यालय 'इंदिरा भवन में हुई इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे.

एक करोड़ के इनामी खूंखार हिड़मा समेत 6 नक्सली ढेर

सुकमा। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा के घने वन क्षेत्र में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई बड़ी मुठभेड़ में एक करोड़ के इनामी नक्सली हिड़मा समेत छह नक्सली मारे गये। जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेडमिल्ली थाना क्षेत्र के पामालेरू जंगल में आज सुबह हुई, जहां पिछले कई दिनों से नक्सलियों की गतिविधि और ठिकाने की सूचनाएं मिल रही थीं। आज सुकमा में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में पीएलजीए कमांडर हिड़मा और उसकी पत्नी के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के अनुसार, कुख्यात माओवादी कमांडर मदवी हिड़मा (43) मारा गया है।

प्रेम कुमार बन सकते हैं बिहार के नए स्पीकर, लगातार 9वीं बार जीते हैं चुनाव

पटना। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। इससे पहले राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। साथ ही जदयू और भाजपा के बीच मंत्रियों के नामों पर चर्चा तेज हो गई। ऐसे में खबर आ रही है कि बीजेपी के सीनियर नेता प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया जा सकता है। दरअसल, भाजपा के वरिष्ठ नेता और लगातार नौवीं बार विधायक बने प्रेम कुमार ने मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा तेज हो गई है प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, यदि बिहार विधानसभा में स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहता है, तो पार्टी मगध क्षेत्र (गया) से आने वाले और अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेम कुमार पर दांव लगा सकती है। प्रेम कुमार पिछले तीन दशकों से लगातार चुनाव जीतते आए है और संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी हाईकमान जल्द ही स्पीकर पद को लेकर नाम अंतिम कर सकता है। यदि पार्टी सामाजिक समीकरण और अनुभव को प्राथमिकता देती है, तो प्रेम कुमार का नाम सबसे आगे माना जा रहा है।

सीएम योगी ने भरा एसआईआर फॉर्म

मतदाताओं से की अपील- मज़बूत लोकतंत्र की नींव बनें

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गणना फॉर्म भरकर आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंप दिया। सीएम योगी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में एसआईआर फॉर्म भरा। एक पोस्ट में, योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मतदाताओं से गणना फॉर्म भरने की अपील की और सत्यापित मतदाताओं को एक मजबूत लोकतंत्र की नींव बताया। योगी ने लिखा कि सत्यापित मतदाता एक मजबूत लोकतंत्र की नींव है। आज, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत, मैंने स्वयं गोरखपुर में अपना

गणना फॉर्म भरकर जमा किया। आप सभी एसआईआर फॉर्म अवश्य भरें। आपका यह छोटा सा प्रयास भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। बिहार में पहले चरण के सफल समापन के बाद, राष्ट्रव्यापी एसआईआर चरण II वर्तमान में अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। गणना चरण, जो 4 नवंबर, 2025 को शुरू हुआ, और 4 दिसंबर, 2025 तक जारी रहेगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित होने वाली है।

बिहार में आज सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक नियुक्त

पटना।

बिहार बीजेपी विधायक दल की मीटिंग के लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया गया है. साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुनराम मेघवाल सह पर्यवेक्षक बनाए गए है. बुधवार (19 नवंबर) सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक पटना में होगी. केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम हैं और बिहार चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी की भूमिका उन्होंने निभाई थी. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. इस बैठक में बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनाव जाएगा. कल का दिन बीजेपी के लिए अहम है. 20 नवंबर को बिहार में शपथ ग्रहण होना है, उससे

पहले तमाम दल अपने विधायकों के साथ बैठक कर लेंगे. सभी दलों की बैठक के बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी. इस बैठक में एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा. जो नेता चुना जाएगा वो राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा. ये सारी प्रक्रिया कल तक पूरी हो जाने की उम्मीद है. सूत्रों के मुताबिक, बिहार में बीजेपी के दो डिप्टी सीएम होंगे. लेकिन वो नाम कौन होंगे, इस पर अभी तक आखिरी मुहर नहीं लग पाई है. सूत्रों की मानें तो सरकार गठन से पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़े मुद्दों पर सहमति बन चुकी है.

चुनावी हार के बाद प्रशांत किशोर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- बिहार सुधार कर रहूंगा, पीछे हटने वाला नहीं

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनावों में भारी हार के बाद पहली प्रतिक्रिया में, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने हार का सारा दोष अपने ऊपर लेते हुए राज्य की जनता से माफ़ी मांगी। अपनी पार्टी की बिहार चुनाव में भारी हार के लिए सारी जिम्मेदारी लेते हुए, जन सुराज पार्टी प्रमुख ने कहा कि वह सरकार बदलने में नाकाम रहे। उन्होंने एक दिन का मौन व्रत भी लिया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से बहुत सकारात्मक प्रयास किया। हम इस सरकार को बदलने में नाकाम रहे। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है हम कहीं न कहीं चूक गए। मैं सारा दोष अपने ऊपर लेता हूं क्योंकि मैं लोगों को समझा नहीं पाया। हम आत्ममंथन करेंगे। मुझे खेद है। किशोर ने कहा

कि गहरा झटका मिला लेकिन हम गलतियों को सुधारेंगे, मजबूत हो कर लौटेंगे, पीछे जाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि जनता ने राजग को जनादेश दिया है, चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम करना मोदी, नीतीश की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता को यह समझाने में नाकाम रहा कि उन्हें किस आधार पर वोट देना चाहिए और नई व्यवस्था क्यों बनानी चाहिए। इसलिए, प्रायश्चित स्वरूप, मैं 20 नवंबर को गांधी भितिहरवा आश्रम में एक दिन का मौन व्रत रखूंगा। उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमने कोई अपराध नहीं किया है। हमने समाज में जाति-पाति का जहर फैलाने का अपराध नहीं किया है। हमने बिहार में हिंदू-मुस्लिम की राजनीति नहीं की है। हमने धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का अपराध नहीं किया है।

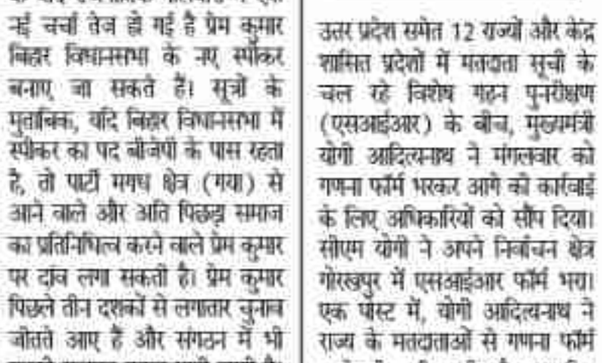

हमने बिहार की गरीब, भोली-भाली जनता को पैसे देकर उनके वोट खरीदने का अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयासों में, हमारी सोच में, और जिस तरह से हमने यह समझाया कि जनता ने हमें नहीं चुना, उसमें जरूर कोई न कोई चूक रही होगी। अगर जनता ने हम पर विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी शत-प्रतिशत अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत सका।

दिल्ली की 4 अदालतों और 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जैश-ए-मोहम्मद के नाम से आया ई-मेल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक फिर से स्कूलों और कोर्ट को बम की धमकी मिली है। दिल्ली के साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस, तीस हजारी और रोहिणी कोर्ट समेत सीआरपीएफ के दो स्कूलों को बम की धमकी मिली है। यह धमकी भरा ई-मेल जैश-ए-मोहम्मद के नाम से आया है। वहीं, जांच के लिए मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने बताया कि ये स्कूल प्रशांत विहार और द्वारका में स्थित है और बम की धमकी वाली कॉल सुबह करीब 9 बजे मिली थी। इस मामले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने दोनों स्कूलों की गहन जांच की और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसे झूठी खबर घोषित कर दिया गया है। सीआरपीएफ स्कूल में मंगलवार को वार्षिक उत्सव चल रहा है। पिछले साल इस स्कूल के पास बम धमाका

हुआ था। सीआरपीएफ स्कूल से कुछ ही दूरी पर स्थित रोहिणी कोर्ट परिसर की भी पुलिस ने बारीकी से तलाशी ली। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों जगहों की सघन तलाशी ली गई, कुछ असामान्य नहीं मिला। साकेत कोर्ट परिसर को खाली कराकर कर अंदर जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए हैं। इस कारण वकीलों की गाड़ी सड़क पर खड़े होने के कारण जाम लग गया। बताया गया कि द्वारका कोर्ट में काम सामान्य चल रहा है। नई दिल्ली बार एसोसिएशन ने पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजामों की जानकारी दी है। एसोसिएशन ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को कोर्ट परिसर में तैनात किया गया है और सभी आवश्यक कदम उठाए गए है ताकि न्यायाधीश, बार के सदस्य, स्टाफ और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एसोसिएशन ने कहा कि हाल ही में प्राप्त बम धमाके की चेतावनी को लेकर बार के सदस्यों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और यदि सुरक्षा कर्मी उनके बैग या व्यक्तिगत सामान की जांच करना चाहें तो सहयोग करें। साथ ही, बार एसोसिएशन ने यह भी कहा कि यदि कोई अनजान या संदिग्ध वस्तु नजर आए, तो तुरंत नजदीकी सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी दी जाए। इस चेतावनी के बाद कोर्ट परिसर और आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आम जनता से भी सहयोग की अपील की गई है।

निकाय चुनाव तक रोक दें एसआईआर, आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार

नई दिल्ली। केरल सरकार ने राज्य में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा वर्तमान में किए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को स्थगित करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका में राज्य ने तर्क दिया है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (एलएसजीआई) के चुनावों के साथ-साथ एसआईआर कराने से गंभीर प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी और चुनावों के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न होगी। राज्य ने स्पष्ट किया कि यद्यपि वह बाद में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, लेकिन वर्तमान याचिका केरल में संशोधन प्रक्रिया को स्थगित करने पर केंद्रित है। केरल में 1,200 स्थानीय निकाय चुनाव (एलएसजीआई) है, जिनमें 941 ग्राम पंचायतें, 152 ब्लॉक पंचायतें, 14 जिला पंचायतें, 87 नगर पालिकाएं और 6 निगम शामिल है, जो कुल मिलाकर 23,612 वार्डों को कवर करते है। चुनाव 9 और 11 दिसंबर को दो चरणों में होने है। एसआईआर 4 नवंबर को शुरू हुआ, और 4 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होनी थी, जिससे पूरे संशोधन को लागू करने के लिए केवल एक महीना बचा है। राज्य का तर्क है कि यह समय-सीमा स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों से गंभीर रूप से टकराती है। याचिका के अनुसार, स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए 68,000 सुरक्षा कर्मचारियों के अलावा 1,76,000 कर्मियों की आवश्यकता है। एसआईआर को ही 25,668 अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता है, जिसके बारे में राज्य का कहना है कि इससे प्रशासनिक मशीनरी पर गंभीर दबाव पड़ता है और नियमित शासन-प्रशासन ठप होने का खतरा है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 243-ई और 243-यू के साथ-साथ केरल पंचायत राज अधिनियम की धारा 38 और केरल नगर पालिका अधिनियम की धारा 94 का हवाला दिया गया है, जो सभी स्थानीय परिषदों की पहली बैठक के पांच वर्षों के भीतर चुनाव कराने का आदेश देते है। नए एलएसजीआई सदस्यों को 21 दिसंबर से पहले शपथ लेनी होगी। इसके विपरीत, केरल का तर्क है कि इस समय विशेष मतदाता सूची संशोधन करने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, और चुनाव आयोग ने तत्काल एसआईआर की आवश्यकता वाले कोई विशेष कारण नहीं बताए है।

महायुति का बड़ा ऐलान: भाजपा-शिवसेना-राकांपा मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव, खत्म हुई अटकलें

मुंबई। पर विराम लगाते हुए, महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को कहा कि महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा, शिवसेना और राकांपा राज्य में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव मिलकर लड़ेंगी। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए, बावनकुले ने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य बीएमसी चुनावों में दो-तिहाई वार्ड और 51 प्रतिशत वोट हासिल करना है। भाजपा नेता ने कहा कि मुंबई नगर निगम चुनावों में, महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमारा लक्ष्य मुंबई नगर निगम में सरकार बनाने के लिए दो-तिहाई सीटें और 51 प्रतिशत वोट हासिल करना है। अटकलों पर विराम लगाते हुए, महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को कहा कि महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा, शिवसेना और राकांपा राज्य में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव मिलकर लड़ेंगी। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए, बावनकुले ने कहा कि गठबंधन का

लक्ष्य बीएमसी चुनावों में दो-तिहाई वार्ड और 51 प्रतिशत वोट हासिल करना है। भाजपा नेता ने कहा कि मुंबई नगर निगम चुनावों में, महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी। हमारा लक्ष्य मुंबई नगर निगम में सरकार बनाने के लिए दो-तिहाई सीटें और 51 प्रतिशत वोट हासिल करना है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीद करती है कि स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ रहे पार्टी कार्यकर्ता अपना नामांकन पत्र वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे सभी

नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए, बावनकुले ने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य बीएमसी चुनावों में दो-तिहाई वार्ड और 51 प्रतिशत वोट हासिल करना है। भाजपा नेता ने कहा कि मुंबई नगर निगम चुनावों में, महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी।

स्वतंत्र भाजपा कार्यकर्ता नामांकन वापस लेने की अंतिम समय सीमा से पहले अपना नामांकन पत्र वापस ले लेंगे। चूंकि किसी विशेष सीट पर केवल एक ही व्यक्ति को एबी फॉर्म दिया जा सकता है, इसलिए बाकी लोगों को निराश नहीं होना चाहिए और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की जीत के लिए काम करना चाहिए। बावनकुले ने कहा, हमारी अपील को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और हमें विश्वास है कि कई लोग अपना नामांकन वापस ले लेंगे। चूंकि चुनाव सात या आठ साल बाद हो रहे है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी को टिकट की उम्मीद होती है। हालांकि, अधिकांश उम्मीदवार नामांकन वापस लेने की अवधि के भीतर उचित निर्णय ले लेंगे। राज्य में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों, यानी कुल 288, के सदस्यों और प्रत्यक्ष अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव के लिए मतदान 2 दिसंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि इन सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 4 नवंबर को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

गुजरात के अरावली में एंबुलेंस में लगी आग; नवजात और डॉक्टर सहित चार की मौत

मोडासा (गुजरात)।

गुजरात के अरावली जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मोडासा कस्बे के पास एंबुलेंस में आग लगने से एक नवजात, एक डॉक्टर और दो अन्य लोगों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस निरीक्षक डीबी वाला ने बताया कि मोडासा-धांसुरा रोड पर एंबुलेंस में आग रात करीब एक बजे आग लगी। एंबुलेंस में बीमार नवजात को मोडासा के निजी अस्पताल से अहमदाबाद के निजी अस्पताल में आगे के उपचार के लिए ले जाया जा रहा था। अधिकारी ने बताया कि नवजात, उसके पिता जिग्नेश मोची (38 वर्षीय), अहमदाबाद के डॉक्टर शांतिलाल रेंटिया (30 वर्षीय) और अरावली की नर्स भूरीबेन मनात (23 वर्षीय) की मौत हो गई। तीन अन्य (मोची के दो रिश्तेदार और एंबुलेंस चालक) झुलस गए और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।